

VIDYA BHAWAN BALIKA VIDYA PITH

शक्ति उत्थान आश्रम लखीसराय बिहार

class 12 commerce Sub. ECO/ B Date 4.6.2020

Teacher name – Ajay Kumar Sharma

LIBERALISATION, PRIVATISATION

AND

GLOBALISATION: AN APPRAISAL

INTRODUCTION

You have studied in the previous chapter that, since independence, India followed the mixed economy framework by combining the advantages of the capitalist economic system with those of the socialist economic system. Some scholars argue that, over the years, this policy resulted in the establishment of a variety of rules and laws, which were aimed at controlling and regulating the economy, ended up instead in hampering the process of growth and development. Others state that India, which started its developmental path from near stagnation, has since been able to achieve growth in savings, developed a diversified industrial sector which produces a variety of goods and has experienced sustained expansion of agricultural output which has ensured food security. आपने पिछले अध्याय में अध्ययन किया है कि, स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने समाजवादी आर्थिक प्रणाली के साथ पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के लाभों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था ढांचे का पालन किया। कुछ विद्वानों का तर्क है कि, वर्षों में, इस नीति के परिणामस्वरूप विभिन्न नियमों और कानूनों की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और विनियमित करना था, विकास और विकास की प्रक्रिया में बाधा डालने के बजाय समाप्त हो गया। अन्य लोगों ने कहा कि भारत, जिसने गतिरोध के निकट से अपना विकास पथ शुरू किया, तब से बचत में वृद्धि हासिल करने में सक्षम है, एक विविध औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है जो विभिन्न प्रकार के माल का उत्पादन करता है और कृषि उत्पादन के निरंतर विस्तार का अनुभव किया है जिसने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।

In 1991, India met with an economic crisis relating to its external debt — the government was not able to make repayments on its borrowings from abroad; foreign exchange reserves, which we generally maintain to import petroleum and other important items, dropped to levels that were not sufficient for even a fortnight. The crisis was further compounded by rising prices of essential goods. All these led the government to introduce a new set of policy measures which changed the direction of our developmental strategies. In this chapter, we will look at the

background of the crisis, measures that the government has adopted and their impact on various sectors of the economy. 1991 में, भारत अपने बाहरी ऋण से संबंधित एक आर्थिक संकट के साथ मिला - सरकार विदेशों से अपने उधार पर पुनर्भुगतान करने में सक्षम नहीं थी; विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम आम तौर पर पेट्रोलियम और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं को आयात करने के लिए बनाए रखते हैं, जो कि एक पखवाड़े तक भी पर्याप्त नहीं थे। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से संकट और बढ़ गया था। इन सभी ने सरकार को नीतिगत उपायों का एक नया सेट पेश करने का नेतृत्व किया, जिसने हमारी विकास रणनीतियों की दिशा बदल दी। इस अध्याय में, हम संकट की पृष्ठभूमि, उपायों को देखेंगे जो सरकार ने अपनाए हैं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर उनका प्रभाव है।